गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 329
दि. 02.04.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

“सरकार ही सबसे बड़ी मुकदमेबाज”: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, अनावश्यक अपीलों पर कड़ा संदेश

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते बोझ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आईना दिखाया है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ही देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज बन चुकी है और उसकी अनावश्यक अपीलों के कारण अदालतों में लंबित मामलों का अंबार लगातार बढ़ता जा रहा है। यह टिप्पणी उस समय आई जब कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया। दरअसल, यह मामला एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के अधिकारी से जुड़ा था, जिसे 11 दिनों तक अनुपस्थित रहने और अनुशासनहीनता के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले की गहराई से जांच करते हुए पाया कि अधिकारी मेडिकल अवकाश पर था और उसके खिलाफ लगाए गए अन्य आरोप भी ठोस आधार पर खरे नहीं उतरते। इस आधार पर हाईकोर्ट ने उसे राहत दी थी। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की। इस मामले की सुनवाई बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ कर रही थी। दोनों जजों ने सरकार से सीधा सवाल किया कि आखिर ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक लाने की

जरूरत क्या है, जब हाईकोर्ट पहले ही तथ्यों के आधार पर फैसला दे चुका है। अदालत ने कहा कि इस तरह की अपीलें न केवल समय की बर्बादी हैं, बल्कि न्यायिक संसाधनों पर भी अनावश्यक दबाव डालती हैं।

कोर्ट ने केवल अपील खारिज कर देने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि केंद्र सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह जुर्माना केवल आर्थिक दंड नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश है कि सरकार को अपनी मुकदमेबाजी की नीति पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर मामलों को बेवजह लंबा खींचना स्वीकार्य नहीं है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि देश की अदालतों में लंबित मामलों के भारी बोझ के लिए सरकार काफी हद तक जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार को हर मामले में अपील करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए और पहले ठोस कानूनी सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि किसी मामले में हाईकोर्ट ने सजा या निर्णय को असंगत मानते हुए राहत दी है, तो उसे बिना ठोस कारण के सुप्रीम कोर्ट तक खींचना न्याय व्यवस्था के हित में नहीं है।

अदालत ने Supreme Court Bar Association के हालिया सम्मेलन का भी उल्लेख किया, जिसमें जस्टिस नागरत्ना ने पहले ही यह चिंता व्यक्त की थी कि सरकार की अत्यधिक मुकदमेबाजी न्याय प्रणाली पर भारी दबाव डाल रही है। कोर्ट ने दोहराया कि इस मुद्दे को केवल बयानबाजी तक सीमित न रखकर नीतिगत स्तर पर बदलाव की जरूरत है।

यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी चिंताजनक नजर आती है। कानून मंत्रालय के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक सरकार से जुड़े करीब 7.14 लाख मामले विभिन्न अदालतों में लंबित थे। इनमें वित्त मंत्रालय के लगभग 1.94 लाख, भारतीय रेलवे के 1.11 लाख और रक्षा मंत्रालय के 94 हजार से अधिक मामले शामिल हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि सरकारी मुकदमों की संख्या न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।

यह पूरा घटनाक्रम केवल एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक समस्या की ओर इशारा करता है, जहां सरकार हर छोटे-बड़े मामले में अपील करने की आदत से बाहर नहीं निकल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त रुख भविष्य के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब न्यायिक प्रणाली को बोझ से मुक्त करने के लिए सरकार को अपनी रणनीति बदलनी ही होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो न केवल अदालतों पर दबाव बढ़ता रहेगा, बल्कि आम लोगों को न्याय मिलने में भी और अधिक देरी होती जाएगी।

अमरावती बनी आंध्र की स्थायी राजधानी: लोकसभा से ऐतिहासिक बिल पारित, सियासत भी तेज

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर वर्षों से चल रहे असमंजस पर विराम लगा दिया है। बुधवार को लोकसभा ने ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026’ को पारित कर दिया, जिसके तहत अमरावती को राज्य की स्थायी और एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता मिल गई। इस बिल को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन मिला, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। इस फैसले के साथ ही आंध्र प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। लंबे समय से राज्य में राजधानी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसे अब संसद के इस निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है। लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने-अपने तर्क रखे, लेकिन अंततः बहुमत से इसे पारित कर दिया गया।

बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है, लेकिन इसके साथ ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि

अमरावती को बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाए। साथ ही उन्होंने विशाखापत्तनम, तिरुपति और कुर्नूल के संतुलित विकास पर भी जोर दिया।

सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने सदन से अपील की कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए, ताकि राज्य को स्थायी राजधानी मिल सके और विकास कार्यों में तेजी आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीएम रमेश ने इसे आजाद भारत के इतिहास में एक अनोखा कदम बताया। उन्होंने कहा कि पहली बार संसद में किसी शहर को राज्य की राजधानी घोषित करने के लिए विधेयक लाया गया है, जिससे भविष्य में किसी भी तरह का विवाद खत्म हो जाएगा।

हालांकि, विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। पार्टी के सांसद पीवी मिथुन रेड्डी ने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अमरावती परियोजना के लिए करीब 34,000 एकड़ भूमि देने वाले किसानों को अब तक उनके वादे के अनुसार लाभ नहीं मिला है और मुआवजे की कोई स्पष्ट समयसीमा भी तय नहीं की गई है।

गौरतलब है कि 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी स्थापित करनी थी। अब इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद अमरावती को कानूनी रूप से राज्य की स्थायी राजधानी का दर्जा मिल गया है।

कानूनी रूप से राज्य की स्थायी राजधानी का दर्जा मिल गया है। यह फैसला केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे जहां एक ओर राज्य में विकास परियोजनाओं को स्पष्ट दिशा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमरावती को किस गति से विकसित किया जाता है और किसानों समेत आम जनता की अपेक्षाओं को किस हद तक पूरा किया जा पाता है।

छोटी बात, बड़ा मुकदमा: CISF कांस्टेबल केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार

जीएनएस)। नई दिल्ली। न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते बोझ के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। एक साधारण सेवा विवाद को शीर्ष अदालत तक ले जाने पर कोर्ट ने न केवल केंद्र की अपील खारिज कर दी, बल्कि 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार स्वयं सरकार है, जो छोटे-छोटे मामलों को भी अनावश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट तक खींच लाती है। यह पूरा मामला CISF के एक कांस्टेबल से जुड़ा था, जिसे 11 दिनों तक बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और एक सहकर्मी की बेटी की शादी में मदद करने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। मामला जब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने तथ्यों का परीक्षण करते हुए पाया कि यह सजा अत्यधिक कठोर है। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल को सेवा में बहाल करने और 25 प्रतिशत पिछला वेतन देने का आदेश दिया।

लेकिन इस फैसले को स्वीकार करने के बजाय केंद्र सरकार ने इसे चुनौती

देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी बात पर सुनवाई कर रही पीठ—बी.वी. नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां—ने कड़ा रुख अपनाया। जस्टिस नागरत्ना ने तीखे लहजे में कहा कि हम अक्सर अदालतों में मामलों के बोझ की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार खुद सबसे बड़ी मुकदमेबाज बन चुकी है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकारी अधिकारियों को यह समझ नहीं आता कि महज 11 दिन की गैरहाजिरी के लिए किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल देना असंगत और अन्यायपूर्ण है।

अदालत ने यह भी कहा कि जब हाईकोर्ट पहले ही मामले में संतुलित और न्यायसंगत फैसला दे चुका था, तो केंद्र सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए था। हर फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करना न केवल न्यायिक समय की बर्बादी है, बल्कि यह आम लोगों के लिए न्याय में देरी का भी कारण बनता है। कोर्ट की यह टिप्पणी केवल एक केस तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उस व्यापक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है, जिसमें सरकारी विभाग बिना पर्याप्त कानूनी विवेक के हर मामले को ऊपरी अदालतों तक ले जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को पूरी तरह खारिज करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना प्रतीकात्मक रूप से एक कड़ा संदेश है कि अदालतें अब अनावश्यक मुकदमों को बर्दाश्त नहीं करेंगी। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि सरकारी अधिकारियों को निर्णय लेने से पहले उचित कानूनी सलाह लेनी चाहिए और केवल जरूरी मामलों में ही अपील करनी चाहिए।

यह फैसला न केवल सरकारी तंत्र के लिए एक चेतावनी है, बल्कि न्यायिक सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। यदि सरकार अपनी मुकदमेबाजी की नीति में बदलाव नहीं करती, तो अदालतों पर बोझ लगातार बढ़ता रहेगा और आम नागरिकों को समय पर न्याय मिलना और कठिन होता जाएगा।

सोशल मीडिया की लत: सुविधा अपने साथ खतरा लेकर आती है, अति से मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होता है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। जब कोई व्यक्ति नशे में चूर हो जाता है, तो उसका विनाश निश्चित है। यानी, बर्बादी। चाहे यह नशा सत्ता का हो, धन का हो, शराब का हो, पद का हो या किसी भी अन्य प्रकार का हो, जब यह हद से अधिक हो जाता है, तो यह अति हमेशा विनाश की ओर ले जाती है।

और यही बात सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। जब इंटरनेट देश और दुनिया में आया, तो हर कोई इसके कार्यों से मोहित हो गया और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। इस इंटरनेट के आगमन से दैनिक जीवन में मानो एक क्रांति आ गई है और जो काम पहले दिनों या घंटों में होता था, वह अब पलक झपकते ही हो जाता है। ईमेल से लेकर ऑडियो-वीडियो तक, ईमेल सहित मीडिया का आदान-प्रदान इतनी तेजी से होने लगा कि सोशल मीडिया के एक नए युग की शुरुआत हो गई और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि के आगमन से ऐसा लगता है कि दुनिया भर की जानकारी आम आदमी की भी पहुंच में आ गई है।

आम आदमी के लिए इस जानकारी का विवेकपूर्ण उपयोग करना स्वाभाविक है, लेकिन इसके दुष्परिणाम अब दुनिया के सामने आने लगे हैं। यह बात निर्विवाद है कि सोशल मीडिया के आगमन से सूचनाओं का प्रवाह अत्यंत बढ़ गया है, सार्वजनिक अभिव्यक्ति के अनेक नए रास्ते खुल गए हैं और रचनात्मकता दिखाने के लिए एक नया मंच मिल गया है। लेकिन यदि सतर्कता और सावधानी नहीं बरती गई, तो प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अक्सर मुसीबत का कारण बन सकती हैं। और दुनिया में यह सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है।

सूरत नगर निगम का रैनबसेरा लापरवाही का शिकार है: सड़क पर बेघर लोग, यातायात संबंधी परेशानी बढ़ गई है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम ने शहर के सशुल्क उपयोग वाले क्षेत्रों की छतों पर बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए वर्षा आश्रय बनाने की पहल की थी। लेकिन निर्माण के बाद भी, रखरखाव की उपेक्षा के कारण, वर्षा आश्रयों की हालत जर्जर मकानों जैसी हो गई है।

अब बात करते हैं कि क्या बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाए गए बसेरा का पूरा मकसद ही नाकाम हो गया है। तस्वीर में दिख रहे परिवार शहर के अलग-अलग इलाकों जैसे सिविल क्रॉसरोड्स, माजुरा गेट, उधना दरवाजा, दिल्ली गेट, वराछा इलाके से गुजरने वाले ओवरब्रिज के नीचे डेरा डाले हुए हैं और पुल के नीचे गंदगी का अड्डा बना रखा है। वहीं दूसरी ओर, गंदे कपड़े पहने हुए परिवार के सदस्यों का सिग्नल के पास खड़ी गाड़ियों पर बोतलों से पानी छिड़कना और गंदे कपड़ों से खिड़कियां साफ करना कोई आम बात नहीं है। और अगर ऐसे दृश्य आम जनता को दिख रहे हैं, तो ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस या नगर पुलिस क्यों नजर नहीं आती? क्या इस तरह की गंदगी को हटाना उनका फर्ज नहीं है? साथ ही, चूंकि खिड़कियां साफ करना और खिड़कियों पर दस्तक देकर भीख मांगना ड्राइवरों का ध्यान भटकाता है, इसलिए इस गंदगी को तुरंत हटाना जरूरी है।

छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। ड्राइवर का ध्यान सिग्नल पर है, ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? चारों सड़कों पर इस तरह गंदगी होना ठीक नहीं है।

चेतंदास साहब का आशीर्वाद: सूरत में सत्य और निडर पत्रकारिता का संदेश

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात के प्रसिद्ध 108वें महंत, जो वर्षों से गोधरा के सांचेलाव रेलवे स्टेशन के सामने स्थित आदिवासी क्षेत्र में उपदेश देकर अपने शिष्यों को व्यसनों से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हजारों लोग उनके दर्शन और सत्संग के लिए उनके आश्रम आते हैं। उनकी अपार कृपा उनके समर्पित शिष्य संतश्री बजरंगदास पर है। संतश्री बजरंगदास 108वें महंतश्री चेतदास साहब आज सूरत स्थित दैनिक समाचार पत्र ‘गरवी गुजरात’ के कार्यालय में आए और ‘गरवी गुजरात’ के पत्रकारों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने जीवन का अर्थ समझाया और अनेक उदाहरणों के माध्यम से मानव जीवन का मार्ग दिखाया। उन्होंने पत्रकारों से निडर और निष्पक्ष रूप से अच्छी बातों को उजागर करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है।

संपादकीय

विवाह बनाम स्वतंत्रता

आधुनिकता के संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे वयस्कों के रिश्तों को लेकर समय-समय पर देश की विभिन्न अदालतों के फैसले सामने आते रहे हैं। उनमें कई विरोधाभास भी नजर आते रहे हैं। इसी तरह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो हालिया फैसलों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवाह संस्था के बीच पैदा हुई नाजुक खाई को ही उजागर किया है। जहां एक मामले में, न्यायालय का कहना था कि वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बना लिव इन रिलेशनशिप, भले ही एक साथी विवाहित हो, अब अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब भले ही विवाह संस्था के पारंपरिक स्वरूप को मानने वाले इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन इससे जुड़े हुए तमाम यक्ष प्रश्न जरूर हमारे सामने हैं। वहीं एक अन्य घटनाक्रम में न्यायालय ने एक ऐसे ही दंपति को संरक्षण देने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर पति या पत्नी के कानूनी अधिकारों को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यह स्पष्ट विरोधाभास वास्तव में एक गहरी कानूनी रिक्तता को ही प्रतिबिंबित करता है। दरअसल, भारतीय कानून ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में, परंपरागत भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने की दिशा में सावधानीपूर्वक ही कदम बढ़ाया है। इसके बावजूद भी, यह विवाह को एक कानूनी रूप से स्वीकृत संस्था के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है। जिसके अंतर्गत वयस्कों के अपने अधिकार और दायित्व भी हैं। निर्विवाद रूप से, जिन्हें आसानी से दरकिनार भी नहीं किया जा सकता है। इस परिणाम के मूल में एक न्यायिक विसंगति भी है। जहां न्यायालय लिव इन रिलेशन को अपराध की श्रेणी से तो बाहर कर देता है, लेकिन उनके परिणामों को वैध ठहराने से हिचकिचाता है। दरअसल, वयस्कों के रिश्तों में यह तनाव सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है।

निर्विवाद रूप से, आज भारतीय समाज एक बड़े संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है। जिसमें भारतीय परंपरागत जीवन मूल्यों तथा तेजी से बदलते रिश्तों के बीच का एक द्वंद्व भी शामिल है। यह एक हकीकत है कि आधुनिक जीवन में रिश्तों में स्वतंत्रता की बयार स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता से परवान चढ़ी है। लेकिन भारत जैसे परंपरावादी समाज में सदियों से विवाह एक अनुबंध होने के साथ-साथ एक गहरी सामाजिक मान्यता भी है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय समाज में आधुनिक रिश्तों की वास्तविकता कहीं अधिक परिवर्तनशील भी है। वयस्कों के रिश्तों में व्यक्ति आगे बढ़ता है, कभी-कभी बिना औपचारिक समापन के भी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि कानून भी मौजूदा परिदृश्य की इस वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। यह भी एक सत्य है कि वयस्कों के रिश्तों को संरक्षण या मान्यता से वंचित करना, ऐसे रिश्तों को समाप्त नहीं करता है। वास्तव में यह केवल उन्हें असुरक्षा और कानूनी अनिश्चितता की ओर धकेल देता है। सही मायनों में आवश्यकता न्यायिक असंगति की नहीं है, बल्कि विधायी स्पष्टता की ही है। वास्तव में एक हकीकत यह भी है कि भारतीय समाज में वैवाहिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने वाले एक प्रभावी ढांचे की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जाती रही है। हमें मौजूदा परिदृश्य में यह बात स्वीकार करनी होगी कि यद्यपि विवाह संस्था संरक्षण की हकदार है, फिर भी पुरुष या स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनिश्चित काल तक इसके अधीन बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, अंततः कानून को एक सरल सत्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि जब रिश्ते टूट जाते हैं, तो व्यक्तियों को गरिमा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देना हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिये खतरा नहीं है। बल्कि यह उसका एक आवश्यक अनुकूलन ही है। ऐसे समय पर जब तकनीक व सूचना क्रांति से पूरी दुनिया एक संस्कृति में ढल रही है, हम अलग-थलग नहीं रह सकते। हमें पीढ़ियों के अंतराल से उपजी सोच का भी सम्मान करना होगा।

विवादों से दूर रह रिश्ते सुधार सकते हैं बालेन

> नेपाल ने लिपुलेख-लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र से संबंधित सवाल सबसे पहले 1991 में भारत के साथ उठाया था। यह मुद्दा उस समय सामने आया जब 1990 में नेपाल में राजशाही से लोकतांत्रिक सरकार में बदलाव हुआ, और नई सरकार ने सुगौली संधि के तहत सीमा निर्धारण पर आपत्तियां जताई थीं।

अच्छा हुआ, नेपाल की पूर्व विदेशमंत्री आरजू राणा भारत में नहीं हैं। वो होतीं, तो शेख़ हसीना जैसा शरण और प्रत्यर्पण वाला इश्यू खड़ा हो जाता। 19 अगस्त, 2024 को जब वो भारत आईं, विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट किया था, 'नेपाल की डॉ. आरजू राणा देउबा का विदेश मंत्री के तौर पर भारत की अपनी पहली यात्रा पर स्वागत है। हम अपनी बातचीत का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।' आरजू राणा की शख्सियत ख़ास इसलिए भी है, क्योंकि वो नेपाल में पांच बार प्रधानमंत्री रह चुके शेरबहादुर देउबा की श्रीमती जी हैं। पिछले महीने, जब नेपाल पुलिस की अनुसंधान शाखा, (सीआईबी) और मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाले महकमे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (डीएमएलएआई) के अधिकारी उन्हें तलाश रहे थे, तब आरजू राणा भारत में थीं।

ये जो कुछ हो रहा है, उसके पटकथा लेखक, पूर्व उपप्रधानमंत्री व पत्रकार रबि लामिछाने हो सकते हैं। मान्यवर, करोड़ों रुपये के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले में जेल में थे। जेन-ज़ी आंदोलन के समय जिन्हें छुड़ाने के क्रम में फायरिंग हुई, और दस क़ैदी मारे गए थे। इस तरह की चर्चा, कि आरएसपी सरकार का मुखिया गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सज़ायाफ्ता रहा है, बालेन्द्र सरकार को असहज कर रही थी। अब यह कह सकते हैं, कि देखो, जो बरसों से सत्ता में रहे हैं, वो भी कोई परमहंस नहीं हैं।बहरहाल, आरजू राणा देउबा को दिल्ली से सिंगापुर, जैसे-तैसे रवाना किया गया। लेकिन, सोमवार को पता चला, कि अब आरजू राणा देउबा हांगकांग में घुटनों के इलाज के लिए गई हैं। यों, नेपाल और हांगकांग के बीच कोई औपचारिक प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। चुनांचे, आरजू राणा देउबा ने सुरक्षित ठिकाना ढूंढ़ लिया है। ख़ैर, जो होता है, अच्छे के लिए होता है। भारत पहले से शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण वाले कूटनीतिक विवाद में उलझा हुआ था, उसके लिए एक नया बखेड़ा नेपाल से शुरू हो जाता। इस समय नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली और नेपाली कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री दीपक खड़का की गिरफ्तारी से माहौल गरमाया हुआ है। अदालत में इसे चुनौती दी गई है, जिसपर सुनवाई सरकार द्वारा जवाब मिलने के बाद होगी। धनशोधन का आरोप पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड पर भी है। मनी लॉन्ड्रिंग के लांछन से मिस्टर एंड मिसेज देउबा, उनके बेटे जयवीर सिंह देउबा, उनके साले भूषण राणा मुक्त नहीं हैं। ये लोग देश से बाहर हैं। लगता है, देउबा कुनबा चैन की सांस नहीं ले पायेगा। राणा काल से ही भारत, नेपाली नेताओं को राजनीतिक शरण देने के वास्ते सबसे सुरक्षित मुकाम माना जाता है।

देउबा विवाद से दिल्ली बच तो गई, लेकिन, यह न मान लें कि मतभेदों से मुक्ति मिल गई। जून, 2026 से 17 हज़ार 500 फीट ऊंचाई वाले दुर्गम लिपुलेख दर्रे के बरास्ते भारत-चीन के बीच व्यापार की शुरुआत होनी है। केपी शर्मा ओली इसका विरोध दर्ज़ कराने पिछले साल पेइचिंग पहुंच गए थे। चीन ने पल्ला झाड़ा, तो कम्युनिस्ट नेता निराश होकर चुप्पी लगा गए। अब नेपाल का नया निज़ाम इसे कैसे हैंडल करता है, यह देखना बाक़ी है। लिपुलेख दर्रे पर नेपाली दावेदारी के वास्ते एक फ़र्जी 'चुच्चे नक्शा' संसद में पास करा लिया गया था। नेपाली में 'चुच्चे' का मतलब 'नुकीला' होता है। लिपुलेख दर्रे की भू-सामरिक स्थिति नुकीली है।

उपलब्ध दस्तावेज़ बताते हैं, भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से होकर गुज़रने वाला यह सबसे प्राचीन व्यापार मार्ग है, जो भारत के उत्तराखंड को तिब्बत के तकलाकोट (पुरंग) से जोड़ता है। सदियों से भोटिया व्यापारी, विशेष रूप से लोग, ऊन, मसाले और कृषि उत्पादों के आदान-प्रदान के लिए इस मार्ग का उपयोग करते आ रहे हैं। उस दौर में भारतीय मसालों, वस्त्रों और गुड़ के बदले तिब्बती ऊन, रेशम और बोरेक्स का आदान-प्रदान 'बार्टर सिस्टम' के ज़रिये किया जाता था। इसे 'कैलास मानसरोवर यात्रा पथ' के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

1962 के भारत-चीन युद्ध में इस मार्ग के बंद होने के बाद, 1992 में इसे व्यापार के लिए फिर से खोला गया, और यह युद्धोपरांत व्यापार के लिए पहली आधिकारिक चौकी बन गया। कठोर मौसमी परिस्थितियों के कारण, यहां आवागमन आमतौर पर जून और सितंबर के बीच ही संचालित होता है। यह चीन के साथ तीन व्यापारिक चौकियों में से पहली थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश का शिपकी ला दर्रा (1994) और सिक्किम के नाथू ला (2006) का नंबर आया।

नेपाल ने लिपुलेख-लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र से संबंधित सवाल सबसे पहले 1991 में भारत के साथ उठाया था। यह मुद्दा उस समय सामने आया जब 1990 में नेपाल में राजशाही से लोकतांत्रिक सरकार में बदलाव हुआ, और नई सरकार ने सुगौली संधि के तहत सीमा निर्धारण पर आपत्तियां जताई थीं। उस समय नेपाली कांग्रेस के नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला देश के प्रधानमंत्री थे। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता, कि यह केवल नेपाली कम्युनिस्टों या प्रतिक्रियावादियों का मुद्दा था। यह मामला 2020 तक धीरे-धीरे सुलगता रहा। मगर, सवाल है, जिस मार्ग से 1962 से पहले भी भारत-चीन व्यापार करते रहे, वह नेपाल का कैसे हो गया?

वर्ष 1816 की सुगौली संधि में लिपुलेख व लिम्पियाधुरा को स्पष्टतया नेपाल का हिस्सा, या भारत का भाग मानने पर विवाद है। नदी के उद्गम स्थल पर दोनों देशों के अलग-अलग दावे हैं, जिस कारण यह क्षेत्र विवादित है। नेपाल का मानना है, कि कुटी घाटी से निकलने वाली नदी (कुटी यांगती) जो मुख्य महाकाली नदी है, के पूर्व का हिस्सा (लिम्पियाधुरा, लिपुलेख व कालापानी) नेपाल का है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि महाकाली का उद्गम कालापानी के पास से होता है इसलिए लिम्पियाधुरा व लिपुलेख उसके क्षेत्र में हैं। कुटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ब्यास घाटी में अंतिम भारतीय गांव है।

लेकिन चीन यदि भारत से लिपुलेख के ज़रिये व्यापार समझौता करता है, तो इसका मतलब वो आधिकारिक रूप से इसे भारत का हिस्सा मान चुका है। ओली जब थ्येनआनमन समारोह में पेइचिंग गए, और इसकी तनक़ीद की, तो चीन ने उसे गम्भीरता से नहीं लिया। सबसे गड़बड़झाला चुच्चे नक्शा है, जिसका ऐतिहासिक आधार नहीं है। नेपाल की संसद के निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) ने कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को शामिल करने वाले विवादित 'चुच्चे नक्शे' (संशोधन विधेयक) को 13 जून, 2020 को सर्वसम्मति से पारित किया था। तत्कालीन नेपाली सांसद सरिता गिरी ने जब चुच्चे नक्शे का स्रोत संसद में मांगा, उनकी सदस्यता किसी और बहाने बर्खास्त कर दी गई। भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 'चुच्चे नक्शे' को चुनौती दे दे, तो नेपाल को क्या भाव बैठेगा?

प्रेरणा

खिड़की से शुरू हुई शिक्षा: अदम्य जिज्ञासा से विश्व पटल तक का सफर

मनुष्य के जीवन में ज्ञान का महत्व सर्वोपरि है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान प्राप्त करने की लगन। जब किसी के भीतर सीखने की तीव्र इच्छा जाग जाती है, तब वह सीमित संसाधनों के बावजूद भी अपने लिए रास्ते बना लेता है। यह कथा एक ऐसे ही बालक की है, जिसकी परिस्थितियाँ साधारण थीं, लेकिन उसके सपने और जिज्ञासा असाधारण थी।

एक छोटे से शहर के विद्यालय में एक दिन अचानक निरीक्षण के लिए एक स्कूल इंस्पेक्टर पहुँचे। उनका उद्देश्य यह देखना था कि बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है और वे कितने सक्षम हैं। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने बच्चों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के एक कठिन प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न इतना जटिल था कि पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। विद्यार्थी एक-दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था।

शिक्षक की स्थिति भी असहज हो गई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। उन्हें चिंता होने लगी कि यदि कोई भी छात्र उत्तर नहीं दे पाया, तो उनकी योग्यता पर सवाल उठ सकता है। वातावरण में तनाव स्पष्ट महसूस किया जा सकता था।

इसी दौरान कक्षा की खिड़की के बाहर एक दुबला-पतला बालक खड़ा दिखाई दिया। उसकी आँखों में चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। वह ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। अचानक वह बिना झिझक के कक्षा के अंदर आ गया और विनम्रता से बोला, "सर, इस प्रश्न का उत्तर मुझे आता है।" यह सुनकर सभी चौंक उठे। एक अनजान बालक, जो इस विद्यालय का छात्र भी नहीं था, वह इतने आत्मविश्वास से उत्तर देने की बात कर रहा था। इंस्पेक्टर ने उसे अनुमति दी। बालक ने बिना रुके और बिना घबराए उस कठिन प्रश्न का उत्तर बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में दे दिया। उसका उत्तर इतना सटीक था कि वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। शिक्षक, विद्यार्थी और इंस्पेक्टर सभी उसकी प्रतिभा को देखकर स्तब्ध थे।

इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, "बेटा, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो?" बालक ने सहजता से उत्तर दिया, "मैं किसी कक्षा में नहीं पढ़ता। मैं तो पास के खेतों में अपनी गाय चराने आता हूँ। जब भी समय मिलता है, मैं इस स्कूल की खिड़की के पास खड़ा होकर आपकी बातें सुनता रहता हूँ। मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जो कुछ भी आप पढ़ाते हैं, मैं ध्यान से सुनता हूँ।" उसकी यह बात सुनकर सभी के मन में एक गहरी भावना जाग उठी। यह बालक बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, केवल सुनकर इतना ज्ञान अर्जित कर चुका था। उसकी लगन और जिज्ञासा ने उसे वहाँ तक पहुँचा दिया था, जहाँ पहुँचने के लिए अन्य बच्चों के पास सभी सुविधाएँ होते हुए भी वे नहीं पहुँच पाए थे।

इंस्पेक्टर ने तुरंत उसकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने उसी समय आदेश दिया कि इस बालक का विद्यालय में प्रवेश कराया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उसे छात्रवृत्ति दी जाए, ताकि उसकी शिक्षा में आर्थिक बाधा न आए। इस प्रकार उस बालक के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उसे न केवल कक्षा में बैठकर पढ़ने का अवसर मिला, बल्कि अपने ज्ञान को और अधिक गहराई से समझने का मौका भी मिला। उसकी लगन पहले से ही मजबूत थी, अब उसे सही दिशा भी मिल गई। वह दिन-रात मेहनत करने लगा और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने लगा।

समय के साथ वह बालक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता गया। उसकी प्रतिभा और परिश्रम ने उसे एक नई पहचान दिलाई। वह केवल एक विद्यार्थी नहीं रहा, बल्कि ज्ञान और न्याय का प्रतीक बन गया। आगे चलकर वही बालक डॉ. राधा बिनोद पाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

डॉ. पाल ने अपने जीवन में अनेक उपलब्धियाँ हासिल कीं। वे एक प्रतिष्ठित न्यायविद् बने और उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी पहचान तब बनी जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टोक्यो ट्रायल आयोजित हुआ। इस ट्रायल में विभिन्न देशों के न्यायाधीशों ने युद्ध अपराधों का निर्णय किया।

जहाँ अधिकांश न्यायाधीश एक ही दिशा में निर्णय ले रहे थे, वहीं डॉ. पाल ने अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने बहुमत से अलग जाकर एक असहमतिपूर्ण निर्णय दिया। उनका मानना था कि न्याय किसी एक पक्ष के दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे निष्पक्ष और सार्वभौमिक होना चाहिए। उनका यह निर्णय साहस, सत्यनिष्ठा और न्याय के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक था। उनके इस फैसले ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय वही है, जो बिना किसी दबाव के, पूरी निष्पक्षता के साथ किया जाए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से असाधारण ऊँचाइयों को छू सकता है।

यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सबसे पहला संदेश यह है कि सीखने की इच्छा सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि हमारे भीतर जिज्ञासा और लगन है, तो हम किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, यह कि समाज को हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को पहचानने और उसे आगे बढ़ने का अवसर देने की आवश्यकता है।

आज के समय में जब शिक्षा के अनेक साधन उपलब्ध हैं, तब भी कई लोग अवसरों की कमी का बहाना बनाते हैं। लेकिन यह कथा हमें सिखाती है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। खिड़की के बाहर खड़ा वह बालक यह साबित करता है कि ज्ञान पाने के लिए केवल एक सच्ची इच्छा की आवश्यकता होती है।

अंततः, यह प्रेरक यात्रा हमें यह समझाती है कि जीवन में सफलता का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। जब लगन, मेहनत और सही अवसर एक साथ मिल जाते हैं, तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। यही इस कथा का सार है और यही वह प्रेरणा है, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

8000 KM दूर बैठा दोस्त भारत के लिए खोलेगा खजाना! इस गरीब देश से मोदी ने गैस भंडार की कौन सी डील कर ली?

ईरान अमेरिका जंग शांत होने की जगह आग पकड़ती जा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त दो समुद्री ट्रेड रूट्स को लेकर बवाल मचा है। स्टेट ऑफ होर्मूज के पास चल रही जंग से दुनिया पहले ही परेशान थी। लेकिन ईरान के समर्थन में यमन के हूती विद्रोहियों ने भी जंग में कदम रख दिया है। जिसकी वजह से रेड सी में मौजूद बाब अल मंदेव स्ट्रेट के बंद होने का खतरा भी पैदा हो गया है। आपको बता दें कि बाब अल मदेब स्ट्रेट बंद हो गया तो पूरा यूरोप बर्बाद हो सकता है। यह शिपिंग लिंक ही एशिया को यूरोप से जोड़ता है। बाब अल मंदेब स्टेट भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस से आने वाला ज्यादातर तेल यहीं से भारत पहुंचता है। लेकिन जिस वक्त इन दोनों समुद्री रास्तों को लेकर दुनिया दहशत में है। ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा रणनीतिक और कूटनीतिक दांव खेल दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत अफ्रीका के एक गरीब मगर नेचुरल रिसोर्सेज से भरे देश में ऐसा खेल कर आया है जिसके बारे में एक-एक भारतीय को पता होना चाहिए। भारत ने एक तरफ तो एलपीजी और पेट्रोल की सप्लाई को जारी रखने का शानदार जुगाड़ ढूंढ लिया है। लेकिन इसी के साथ भारत ने दो बेहतरीन ट्रेड रूट्स भी तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारत अब किस नए रूट से एलपीजी गैस ला रहा है। भारत ने एलपीजी गैस के लिए अफ्रीका महाद्वीप में एक नया कतर ढूंढ लिया है। भारत की सरकारी कंपनियां अफ्रीकी देश अंगोला की सरकारी कंपनी सुनानगोल से एलपीजी इंपोर्ट्स शुरू करने जा रही है। अंगोला अफ्रीका का एक गरीब देश जरूर है लेकिन इस देश के पास 11 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के भंडार हैं। भारत पहले से ही अंगोला के साथ थोड़ा बहुत गैस और तेल व्यापार करता रहा है। जिससे दोनों देशों के बीच कनेक्शन बना रहे। अब यही कनेक्शन भारत के काम आ रहा है। भारत का 90% एलपीजी आयात ठप होने की कगार पर है। दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। स्थिति कंट्रोल में रहे उसके लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। तमाम देशों से बातचीत चल रही है। पर्दे के पीछे ईरान से बातचीत कर हॉर्मूज से धीरे-धीरे गेट खुलवाकर भारत के जहाज निकलवाए जा रहे हैं। लेकिन क्या तीन से चार चार से पांच जहाजों का आना काफी है? बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ युद्ध थमता नजर नहीं दिख रहा है बल्कि और भी भयानक होता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत के करोड़ों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे या फिर भारत ने इस संकट का कोई ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जो दुनिया को हैरान करे। क्योंकि अब भारत की नजरें खाड़ी देशों से हटकर एक नए और अनजान दोस्त पर आकर टिक गई है। दरअसल जब हॉर्मूज के दरवाजे बंद हुए तो भारत ने अपने पुराने दोस्तों और नए रास्तों की ओर हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया।

भारत ने अर्जेंटीना से लेकर अमेरिका और नॉर्वे से लेकर रूस तक से गैस मंगानी शुरू कर दिया। लेकिन इसमें दूरी और समय बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका से गैस आने में हफ्तों लग जाते हैं। जब देश में मांग चरम पर है। इतनी दूरी से आने वाली सप्लाई ऊंट के मुंह में जीरे जैसा सामान है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक और चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है। तो ऐसे में सरकार की पूरी मशीनरी इस कोशिश में जुटी है कि किसी भी कीमत पर सप्लाई चेन टूटने ना पाए। कतर और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक ठिकानों से संपर्क कटने के बाद भारत की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और गेल अब ग्लोबल मार्केट में एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रही हैं जो संकट के इस समय में भारत की ढाल बन सके। और यहीं से शुरू होता है एक नया अध्याय। एक ऐसा नाम जो अब तक सिर्फ तेल और हीरों के लिए जाना जाता था। लेकिन अब वो भारत की रसोई का रखरखाव करने जा रहा है। इस पूरे संकट के बीच एंट्री हुई है अफ्रीका के दिग्गज देश अंगोला की। जी हां, वही अंगोला जो नाइजीरिया के बाद अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है।

भारतीय ऊर्जा कंपनियां अब अंगोला की सरकारी कंपनी सोनान गोल के साथ हाई लेवल बातचीत कर रही हैं। और यह डील साधारण नहीं होगी। अगर यह बातचीत सफल हो जाती है तो अंगोला भारत को कुकिंग गैस सप्लाई करने वाला पहला मध्य अफ्रीकी देश बन जाएगा। लेकिन अंगोला ही क्यों? इसका जवाब छिपा है भूगोल और गणित। एक्सपर्ट का मानना है उत्तरी अमेरिका के मुकाबले अंगोला से भारत तक गैस पहुंचने में 10 से 15 दिन कम लगेंगे। यह 15 दिन भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे। अंगोला के पास 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वित्त वर्ष 2025 में अंगोला ने भारत को पहले ही 924 मिलियन की एलएजी सप्लाई की है। अब इसी दोस्ती को एलपीजी तक ले जाने की तैयारी है। यह सिर्फ एक बिजनेस रील नहीं है बल्कि एक कूटनीतिक जीत है। जहां एक तरफ हॉर्मूज में बारूद बरस रहा है। हॉर्मूज का रास्ता बंद पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने हजारों मील दूर अफ्रीका में अपनी ऊर्जा सुरक्षा का नया किला तैयार कर लिया है। 8000 किमी की दूरी है हवाई। तो सोचिए कितना डिस्टेंस पड़ रहा है। भारत और अंगोला का रिश्ता आज का नहीं है। इसकी जड़े 1985 में जमी थी। आज अंगोला में करीब 8000 भारतीय वहां की अर्थव्यवस्था की रीड बने हुए हैं। चाहे वो रिटेल हो, खेती हो या हॉस्पिटिलिटी।

अभियान

आस्था की सीढ़ियाँ और शांति का शिखर: पालीताणा की आध्यात्मिक विराटता का गहन अनुभव

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ स्थान ऐसे हैं, जहाँ पहुँचते ही मनुष्य के भीतर एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पालीताणा ऐसा ही एक दिव्य तीर्थ है, जो केवल दर्शन का स्थल नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का आरंभ है। शत्रुंजय पर्वत की ऊँचाइयों पर बसे इस नगर को 'मंदिरों का शहर' कहा जाता है, लेकिन इसकी असली पहचान उससे कहीं अधिक व्यापक है—यह भक्ति, कला, तप और अहिंसा का जीवंत संगम है।

पालीताणा की विशेषता यह है कि यहाँ की यात्रा बाहरी से अधिक आंतरिक होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस पवित्र भूमि पर कदम रखता है, उसके भीतर एक अलग ही शांति का संचार होने लगता है। यहाँ का वातावरण इतना निर्मल और संतुलित है कि मन स्वतः ही ध्यान की अवस्था में पहुँच जाता है। यह केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है, जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है।

शत्रुंजय पर्वत, जो इस तीर्थ का केंद्र है, जैन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 23 ने इस पर्वत को अपनी उपस्थिति से पवित्र किया। विशेष रूप से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है, का इस स्थान से गहरा संबंध है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ अनेक बार तपस्या की और अपने उपदेशों से इस भूमि को आध्यात्मिक चेतना से भर दिया। यही कारण है कि यह स्थान 'शाश्वत तीर्थ' के रूप में प्रतिष्ठित है।

पालीताणा की यात्रा की सबसे अनूठी बात है इसकी कठिनाई, जो इसे और भी पवित्र बनाती है। पर्वत की चोटी तक पहुँचने के लिए लगभग 3,500 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यह यात्रा केवल शारीरिक प्रयास नहीं, बल्कि एक प्रकार की साधना है। श्रद्धालु प्रातःकाल से ही इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और कई लोग इसे मौन व्रत तथा उपवास के साथ पूर्ण करते हैं। जैसे-जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, उनका मन सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता जाता है और वे एक आध्यात्मिक शांति के करीब पहुँचते जाते हैं।

शत्रुंजय पर्वत पर स्थित मंदिरों की भव्यता इस तीर्थ को विश्व में अद्वितीय बनाती है। यहाँ लगभग 900 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें 17,000 से भी अधिक प्रतिमाएँ स्थापित हैं। इन मंदिरों की संरचना संगमरमर से की गई है और उनकी नक्काशी इतनी सूक्ष्म और अद्भुत है कि देखने वाला आश्चर्यचकित रह जाता है। प्रत्येक मंदिर एक कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक है, जिसमें भारतीय शिल्पकला की उच्चतम परंपरा झलकती है।

इन मंदिरों में आदिश्वर मंदिर सबसे प्रमुख है, जो पर्वत की सबसे ऊँची चोटी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है और इसकी भव्यता अद्वितीय है। यहाँ पहुँचकर श्रद्धालु एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करते हैं, मानो वे अपने भीतर की शांति को पा चुके हों।

चौमुख मंदिर भी यहाँ की विशेष पहचान है। यह मंदिर चारों दिशाओं में खुला हुआ है, जिससे भगवान के दर्शन हर दिशा से किए जा सकते हैं। यह संरचना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान हैं और हर दिशा में उनकी उपस्थिति है। यह मंदिर न केवल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह आध्यात्मिक दर्शन का भी प्रतीक है।

पालीताणा के मंदिरों को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है, जिन्हें 'टूंक' कहा जाता है। प्रत्येक टूंक का अपना अलग महत्व और इतिहास है। कुमारपाल टूंक और विमलशाह टूंक विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन टूंकों में स्थित मंदिरों की नक्काशी इतनी बारीक है कि हर आकृति जीवंत प्रतीत होती है।

पालीताणा केवल भव्य मंदिरों का समूह नहीं है, बल्कि यहाँ कई छोटे-छोटे पवित्र स्थल भी हैं, जो इस तीर्थ की आध्यात्मिकता को और गहरा बनाते हैं। पुंडरीक स्वामी का मंदिर, अष्टपद मंदिर, रायण वृक्ष और भरत चक्रवर्ती से जुड़े स्थल यहाँ विशेष महत्व रखते हैं। प्रत्येक स्थान का अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है और श्रद्धालु यहाँ आकर विशेष अनुभूति प्राप्त करते हैं।

रायण वृक्ष के बारे में यह मान्यता है कि भगवान आदिनाथ ने इसके नीचे तपस्या की थी। यह स्थान आज भी भक्तों के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ बैठकर ध्यान करने से मन को अद्भुत शांति मिलती है।

पालीताणा के नियम इसकी पवित्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति को पर्वत पर रुकने की अनुमति नहीं है। यह माना जाता है कि रात के समय यह स्थान देवताओं का निवास बन जाता है। इस नियम का पालन सख्ती से किया जाता है, जिससे इस तीर्थ की पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहती है।

पालीताणा की एक और महत्वपूर्ण पहचान है—यह विश्व का पहला कानूनी रूप से शाकाहारी शहर है। वर्ष 2014 में यहाँ मांसाहार, अंडे और पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यह निर्णय जैन धर्म के मूल सिद्धांत 'अहिंसा परमो धर्मः' का जीवंत उदाहरण है। यहाँ का हर निवासी और आगंतुक इस नियम का पालन करता है, जिससे पूरे शहर में करुणा और दया का वातावरण बना रहता है।

यह केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है कि मनुष्य यदि चाहे तो अपने जीवन को अधिक संवेदनशील और नैतिक बना सकता है। पालीताणा यह दर्शाता है कि अहिंसा केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवनशैली हो सकती है।

पालीताणा की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति बाहरी सुख-सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। यहाँ का हर अनुभव हमें अपने भीतर झांकने और अपने अस्तित्व को समझने के लिए प्रेरित करता है।

यह तीर्थ केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन में शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति की तलाश में है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लेकर लौटता है।

अंततः, पालीताणा केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभूति है—एक ऐसी अनुभूति, जो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती। यह वह भूमि है जहाँ हर कदम एक नई सीख देता है, हर दृश्य आत्मा को स्पर्श करता है और हर क्षण हमें अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराता है।

शत्रुंजय पर्वत की ऊँचाइयों पर स्थित यह पवित्र धाम आज भी लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की सीढ़ियाँ केवल पत्थरों की नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और समर्पण की प्रतीक हैं। जो भी इस मार्ग पर चलता है, वह केवल पर्वत की चोटी तक ही नहीं, बल्कि अपने आत्मिक शिखर तक भी पहुँच जाता है।

पालीताणा की यह आध्यात्मिक महागाथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है और उसे सही दिशा में प्रयुक्त करता है, तब वह अपने जीवन को एक नई ऊँचाई पर ले जा सकता है। यही इस पवित्र स्थल का सबसे बड़ा संदेश है और यही इसकी अमर पहचान है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

उपलब्धियों भरा वर्ष 2025-26

697 करोड़ रु से अधिक यात्री राजस्व अर्जित, 297 किलोमीटर कवच से लैस,ट्रेनों की पंक्चुअलिटी रही अव्वल,10 स्टेशन बने नेट जीरो स्टेशन

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025 -26 में परिचालन, यात्री सेवा,अवसंरचना, राजस्व एवं सुरक्षा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मंडल के विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों ने इसे एक उत्कृष्ट प्रदर्शन वर्ष बनाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वडोदरा मंडल ने ट्रेन परिचालन में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं। यात्री सुविधा हेतु वडोदरा–कठाना मेमू सेवा पुनः प्रारंभ की गई एवं मियागाम कर्जन -डभोई - प्रतापनगर डेमू का ट्रायल रन किया गया। ट्रेन संख्या 20945 एकतानगर–निजामुद्दीन एक्सप्रेस के समय एवं दिन यात्रियों की मांग के अनुसार परिवर्तित किए गए। प्रतापनगर को वडोदरा का सैटेलाइट स्टेशन के रूप में कमीशन किया गया। मंडल पर ट्रेनों की समयपालनता (पंचुअलिटी) पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा 91.14% रही, तो वहीं फ्रेट ट्रेन की औसत गति 23.89 किमी/घंटा रही, जो अब तक का सर्वाधिक है। माल ढुलाई में मंडल ने 13.46 मिलियन टन लोडिंग के साथ अपने लक्ष्य को हासिल किया।फर्टिलाइजर और कंटेनर लोडिंग में नए आयाम स्थापित किये गए और कंटेनर, कास्टिक सोडा और उर्वरकों की लोडिंग में वृद्धि दिखाई है। 31 मार्च को 33 रेक और 1397 वैगनों की एक दिन में सर्वाधिक लोडिंग दर्ज की गई। नबीपुर में नया गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया और वडोदरा मंडल पर पहली बार फ्रेट कस्टमर्स के लिए बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया।

वर्ष 2025 -26 में मंडल ने 697.57 करोड़ का यात्री राजस्व अर्जित किया गया, जो अभी तक का सर्वाधिक है। इसके साथ ही संड्री, नॉन-फेयर एवं पार्किंग राजस्व में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। नॉन-फेयर रेवेन्यू के अंतर्गत 7.23 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं, जो पिछले वर्ष की सामान अवधि की तुलना में 4.47% अधिक है। रेल मदद शिकायतों में 112% कमी तथा निस्तारण समय में 60% सुधार दर्ज किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 5 स्टेशनों का उद्घाटन किया गया, जो स्टेशन आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत गोधरा स्टेशन भी तैयार है। यात्री सुविधा हेतु डेरोल में 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज यात्रियों के लिए उपलब्ध है तथा 8 अन्य 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 6 मीटर चौड़े 4 अन्य फुट ओवर ब्रिज पूर्ण किए गए। 20 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्मों को विस्तारित या उसकी ऊँचाई बढ़ाने के कार्य किये गए। हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में 2.722 MWp क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किए, जिससे 3.64 मिलियन यूनिट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन किया गया और लगभग 2.92 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाकर 10 स्टेशनों को नेट जीरो स्टेशन बनाया गया।

ट्रेन संचालन की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता में सुधार हेतु 301.1 किमी पुराने एवं कमजोर ओवरहेड उपकरण (OHE) का प्रतिस्थापन किया गया।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025 -26 में 2362 वैगनों का रिकॉर्ड ROH आउटटर्न हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 58.35% अधिक है।

संरक्षा को मजबूत बनाते हुए 17 लेवल क्रॉसिंग को समाप्त किया गया, 5 रोड ओवर ब्रिज एवं 3 रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया तथा 15 पुलों का पुनर्वास किया गया।

297 किमी ट्रैक पर कवच प्रणाली स्थापित कर ट्रेन संरक्षा को और मजबूत किया गया, जिसमे 126 किलोमीटर उत्राण से वडोदरा, 96 किलोमीटर वडोदरा से अहमदाबाद और 76 किलोमीटर वडोदरा से गोधरा खंड शामिल है। कोसंबा, कुंधेला, डेकाकुंड एवं तिलकवाड़ा स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की स्थापना की गयी। यात्री सुविधा के लिए विश्वामित्री, मियागाम करजन, डेरोल एवं डाकोर में कोच गाइडेंस सिस्टम स्थापित किए गए। साथ ही 42 स्टेशनों पर 679 CCTV कैमरे लगाए गए।

यात्रियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए हमारा रेल सुरक्षा बल हमेशा तत्पर है। रेल सुरक्षा बल द्वारा ट्रेस पासिंग के अभियान चलाकर अनधिकृत रूप से रेलवे लाइन को पार करने वाले लोगों के खिलाफ कुल 7901 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया , इससे ट्रेसपासिंग और रन ओवर के मामलों में कमी आई है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 103 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया, जबकि ऑपरेशन अमानत के तहत 1.73 करोड़ मूल्य की 1049 वस्तुएं यात्रियों को लौटाई गईं।

स्क्रैप निपटान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए मंडल ने 78.67 करोड़ का स्क्रैप विक्रय किया जो लक्ष्य से 31% अधिक है। यह उपलब्धि मिशन जीरो स्क्रैप के अंतर्गत वडोदरा मंडल की अपने सभी प्रतिष्ठानों एवं इकाइयों को स्क्रैप-मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

वडोदरा मंडल की ये उपलब्धियां इसकी कार्यकुशलता, सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता, नवाचार एवं यात्री सेवा के उच्च मानकों को दर्शाती हैं। मंडल निरंतर प्रगति करते हुए भारतीय रेलवे में उत्कृष्टता के नए मानदंड स्थापित कर रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने देवका विद्यापीठ के नवनिर्मित कन्या छात्रावास और भोजनालय के अत्याधुनिक सुविधा युक्त भवन का लोकार्पण किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- पूरे राज्य में साधारण और गरीब परिवार के बेटे-बेटियां पढ़-लिखकर आगे बढ़ सकें, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की है
- राज्य में 'कन्या केळवणी महोत्सव' के कारण बेटियों की स्कूल ड्रॉपआउट दर घटकर 2 फीसदी तक नीचे आ गई

- **देवका विद्यापीठ में दानदाताओं के सहयोग से 1100 बेड का गर्ल्स हॉस्टल और 580 छात्राओं की क्षमता वाला अत्याधुनिक सुविधा युक्त भवन तैयार**
- **भागवत कथाकार पू. भाईश्री रमेशभाई ओझा, चापरड़ा गुरुकुल के संचालक श्री मुक्तानंद बापू, जल संसाधन मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल और राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया की विशेष उपस्थिति**

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को अमरेली जिले की राजुला तहसील में स्थित देवका विद्यापीठ में नवनिर्मित अत्याधुनिक कन्या छात्रावास और भोजनालय के नए भवन का पट्टिका अनावरण कर लोकार्पण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान गुजरात में कन्या केळवणी (शिक्षा) की मजबूत नींव रखी थी। साधारण और गरीब परिवार के बेटे-बेटियां पढ़-लिखकर आगे बढ़ सकें, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की है।

शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी महोत्सव की सफल गाथा पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए कन्या केळवणी महोत्सव और शाला प्रवेशोत्सव के कारण बेटियों की ड्रॉपआउट दर घटकर 2 फीसदी तक नीचे आ गई है। राज्य सरकार ने 'नमो लक्ष्मी' और 'नमो सरस्वती विज्ञान साधना' योजनाएं शुरू की हैं, ताकि बेटियों को आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई अधूरी न छोड़नी पड़े। राज्य में अब तक नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 21.34 लाख बेटियों को 1438 करोड़ रुपए की सहायता का लाभ पहुंचाया गया है। इसके अलावा, नमो सरस्वती योजना के तहत 2.96 लाख छात्राओं को 220 करोड़ रुपए की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि गुजरात की बेटियां शिक्षा सहित खेल, स्टार्टअप, अनुसंधान और प्रशासन सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने देवका विद्यापीठ में शिक्षा के साथ-साथ जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण, गीता पाठ और संस्कार सिंचन जैसे राष्ट्रीय मूल्यों के निर्माण के शैक्षणिक यज्ञ की एक अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य के रूप में सराहना की और पू. भाईश्री रमेशभाई ओझा और देवका विद्याधाम को बधाई दी। देवका विद्यापीठ के प्रणेता और भागवद् कथाकार पू. भाईश्री रमेशभाई ओझा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उस राष्ट्र के बालक होते हैं। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में कमजोर प्रदर्शन करने वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करने के लिए तैयार होना जरूरी है। शिक्षा ही विद्यार्थियों में क्षमताओं का निर्माण करती है।

पू. भाईश्री ने भारत की क्षमताओं को दुनिया की श्रेष्ठ क्षमताओं में से एक बताते हुए उसकी सराहना की और कहा कि भारत आज विश्व फलक पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

उल्लेखनीय है कि देवका विद्यापीठ का लोकार्पण वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल, राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे।

देवका विद्यापीठ गर्ल्स हॉस्टल और भोजनालय के नए भवन के लोकार्पण अवसर पर देवका विद्यापीठ के श्री सूर्यकांत ओझा, गौतमभाई ओझा सहित न्यासीगण, चापरड़ा गुरुकुल के संचालक श्री मुक्तानंद बापू, विधायक श्री हीराभाई सोलंकी, श्री महेशभाई कसवाला सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (दक्षिण गुजरात एवं मध्य गुजरात) 1 मई से होगा प्रारंभ इस VGRC में कुल 16 जिले भाग लेंगे

जीएनएस)। गांधीनगर : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन तथा गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल के सक्षम नेतृत्व में दक्षिण एवं मध्य गुजरात क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (VGRC) का आयोजन 1 और 2 मई 2026 को सूरत में किया जाएगा।

VGRC का उद्देश्य क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्र-विशिष्ट निवेश आकर्षित करना और "विकसित भारत@2047" के दृष्टिकोण के अनुरूप वैश्विक सहभागिता को सुदृढ़ करना है। इन सम्मेलनों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि स्थानीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्हें सशक्त किया जा सके तथा उन्हें व्यापक बाजार पहचान और साझेदारियाँ प्राप्त हों। ये क्षेत्रीय सम्मेलन न केवल क्षेत्रीय उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और नई पहलों की घोषणा करने के मंच होंगे, बल्कि राज्यभर में नवाचार को प्रोत्साहित करने, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाने और रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देने के माध्यम से गुजरात की विकास गाथा को आगे बढ़ाने का साधन भी बनेंगे।

VGRC के परिणामों को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के अगले संस्करण में प्रदर्शित किए जाने की अपेक्षा है।

इस VGRC के दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र के भरूच, डांग, नवसारी, सूरत, तापी और वलसाड तथा मध्य गुजरात क्षेत्र के अहमदाबाद, आणंद, छोटा उदेपुर, दाहोद, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, नर्मदा, पंचमहाल और वडोदरा जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों पर सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स एवं अपैरल्स, जेम्स एवं ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम, एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग, ESDM, IT एवं ITeS, बायोटेक/बायोफार्मा, एयरोस्पेस एवं डिफेंस, फिनटेक, ऑटो एवं ऑटो कंपोनेंट्स, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, MSMEs तथा पर्यटन एवं संस्कृति शामिल हैं।

विशेष रूप से, यह VGRC गुजरात स्थापना दिवस के अवसर के साथ आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के साथ-साथ वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल रिवर्स बायर-सेलर मीट और उद्यमी मेला जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे।

उत्तर गुजरात क्षेत्र के लिए VGRC का आयोजन 9 और 10 अक्टूबर 2025 को मेहसाणा स्थित गणपत विश्वविद्यालय में किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल द्वारा किया गया था, जिसमें उत्तर गुजरात के प्रमुख क्षेत्रों जैसे एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग, ऑटो एवं ऑटो कंपोनेंट्स, ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम और इंजीनियरिंग को प्रमुखता दी गई थी।

इस VGRC का उद्देश्य लक्षित निवेश आकर्षित करना और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना था, जिससे गुजरात के जमीनी स्तर के उद्योगों को सशक्त किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कच्छ एवं सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए VGRC का उद्घाटन किया था, जो 11 और 12 जनवरी 2026 को राजकोट स्थित मारवाड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था। इस आयोजन में जापान, दक्षिण कोरिया, रवांडा और यूक्रेन साझेदार देशों के रूप में शामिल हुए थे। इस VGRC के प्रमुख क्षेत्रों में सिरेमिक्स, इंजीनियरिंग, पोर्ट्स एवं लॉजिस्टिक्स, फिशरीज, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग, मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम शामिल थे।

"भक्त शिरोमणि रामदूत हनुमान"

जीएनएस)। राम नाम के अनन्य प्रेमी भक्त शिरोमणि अंजनीसुत हनुमानजी की महिमा से भला कौन परिचित नहीं है। रामायण की कल्पना रामदूत हनुमान के बिना नहीं की जा सकती। भक्त और भक्ति की उत्कृष्टता को सिद्ध करने वाले हनुमानजी की लीला न्यारी है। श्रीराम दूत हनुमान भक्ति की उच्च पराकाष्ठा को सिद्ध करते है इसी कारण श्रीराम भी सदैव उनके साथ ही अपनी पूर्णता को प्रदर्शित करते है, इसीलिए उन्हें भक्त शिरोमणि की भी संज्ञा दी गई है। रामायण में हनुमानजी का नहीं श्रीराम दूत के नवीन रूप का अवतरण हुआ, जो हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सेवा, भक्ति, कर्मों एवं प्रयासों से नवीन स्वरूप में संसार के समक्ष प्रत्यक्ष हो सकते है। महादेव के अंश रुद्रावतार ने श्रीराम के प्रति अनन्य भक्ति एवं प्रेम को हृदय में विराजमान किया। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, यही गुण उनके रुद्रावतार हनुमानजी के स्वभाव में परिलक्षित होता है। वे भी प्रभु श्रीराम की प्रसन्नता के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर धारण करते है।

जहाँ धन, पद और यश के लालच में व्यक्ति अपना सुख चैन, सर्वस्व त्याग देता है, वहीं हनुमानजी ने प्रभु श्रीराम के आग्रह पर उनके चरणपद ही माँग लिए और बाकी सबका सहज ही त्याग कर दिया। हनुमानजी की अनूठी विशेषता उनका अहंकार शून्य होना भी है। हनुमानजी की प्रतिभा संपन्नता तो हमें बाल्य रूप से ही दिखाई देने लगती है। भूख लगने पर सूर्य को फल समझकर खा लेना, उनकी अद्भुत शक्ति संपन्नता को प्रदर्शित करता है, परंतु अपने सम्बोधन में वे रामदूत के उच्चारण को ही प्राथमिकता देते है। हनुमानजी में यदि सेवा भाव एवं पूर्ण समर्पण था, तो वहीं श्रीराम भी हनुमान के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमानजी की एक और विलक्षण विशेषता यह है कि वे अपना परिचय सदैव श्रीराम के दूत के रूप में देते है।

हनुमानजी इतने बुद्धिमान है कि उन्हें ज्ञात है कि कब उन्हें लघु रूप धारण करना है और कब वृहद रूप धारण करके श्रीराम के कार्यो को शीघ्रता से सम्पन्न करना है। हमें सदैव अपने कार्य के प्रति उत्साह का भाव दिखाना चाहिए। जब

श्रीराम के कार्य को पूरा करने के लिए हनुमान समुद्र पार करने गए तो वे अत्यंत उत्साहित थे और लक्ष्य के प्रति दृढ़निष्ठ थे। जब मैनाक पर्वत ने उन्हें रुकने को कहा तो उन्होने कहा मुझे शीघ्रता से माता सीता का पता लगाना है और तत्परता से श्रीराम का कार्य करना है। कार्यों को प्राथमिकता देना भी हमें हनुमानजी से सीखना चाहिए।

श्रीराम दूत हनुमान के जीवन में भक्ति और शक्ति का अनूठा समन्वय दृष्टिगोचर होता है। रामायण का प्रत्येक चरित्र अद्भुत है, परंतु रामायण के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य को पूर्णता हनुमानजी ने दी। समुद्र लाँघना हो, माता सीता का पता लगाना हो, लंका दहन करना हो या लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करनी हो, यह सभी कार्य हनुमानजी के द्वारा पूर्णता को प्राप्त हुए; फिर भी वे प्रत्येक कार्य की सफलता का श्रेय श्रीराम को देते है। हनुमानजी के गुण स्वरूप कार्यों एवं आदर्शों के अनुरूप ही उनके बारह नाम है, जो मनुष्य को अदम्य साहस और ऊर्जा प्रदान करते है। हनुमान, अंजनीसुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुनसखा, पिङ्गाक्ष, अमितविक्रम, सीताशोकविनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीवदर्पहा इन सभी नामों को स्मरण करने से जीवन के पाप और संताप नष्ट होते है। कलयुग में हनुमान चालीसा और सुंदरकाण्ड तो हनुमानजी की कृपा प्राप्ति के लिए भक्तो के अमोघ शस्त्र है। हनुमान चालीसा की उत्कृष्टता तो इस बात में निहित है कि स्वयं गौरी के ईश महादेव उसके साक्षी बनते है। हनुमान चालीसा भी हममे अदम्य शक्ति, साहस, भक्ति एवं ऊर्जा का अंकुरण करती है।

श्रीरामकथा श्रवण के प्रेमी हनुमानजी सदैव श्रीराम के नाम स्वरूप एवं गुणों का दर्शन करते है। यदि हम जीवन के उपवन में भक्ति एवं प्रसन्नता के प्रसून को पल्लवित और पुष्पित करना चाहते है तो असाध्य कार्य को भी साध्य करने वाले रामभक्त हनुमान की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। अद्वितीय भक्ति की प्रतीक माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि और नव निधि का आशीष दिया है। हनुमानजी की विलक्षण लीला हमें शिक्षा देती है कि व्यक्ति के जीवन में कर्म ही प्रधान होते है। उन्हीं कर्मो की वजह से हनुमानजी श्रीराम को भरत एवं लक्ष्मण के समान प्रिय हुए। हनुमानजी की आत्मा की सुंदरता तो माता जानकी और श्रीराम के उनके हृदय में विराजमान होने से है।

भक्त शिरोमणि हनुमान भगवान और भक्ति सब कुछ प्रदान करने का सामर्थ्य रखते है। संसार के प्रत्येक दुर्गम कार्य को सुगमता से करने की क्षमता हनुमानजी में है। श्रीराम दूत के सम्बोधन से तो वे अति प्रसन्न हो जाते है और भक्त पर अपनी विशेष कृपा करते है। स्वयं उत्तम चरित्र से शोभायमान हनुमानजी हमेशा श्रीराम के चरित्र को सुनने के लिए लालायित रहते है। समस्त सद्गुणों के स्वामी हनुमानजी संकट मोचक है।

हनुमान जन्मोत्सव जैसे उत्सव हममे भक्ति की अनूठी ऊर्जा का संचार करते है। अक्सर सांसरिक मोहमाया से भगवान की स्मृति खो देते है, परंतु प्रत्येक उत्सव हममे भगवान की स्मृति को जीवंत करता है। महाभारत में जब कुंती ने श्रीकृष्ण से दुःख मांगा तब श्रीकृष्ण ने कहा की आपका पूरा जीवन अथक संघर्षों में व्यतीत हुआ इसके पश्चात भी आप दुःख माँग रही है। तब उन्होने गोविंद को उत्तर दिया की दुःख में सदैव आपकी स्मृति बनी रहती है। इसी प्रकार यह छोटे-छोटे उत्सव हमें भगवान के नाम रूपी बैंक में निवेश करने को प्रेरित करते है, जोकि मनुष्ययोनि की सच्ची कमाई है। तो आइये उन्हीं श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि हनुमानजी के जन्मोत्सव को पूर्ण हर्षो-उल्लास से मनाए। भक्ति में भाव की प्रधानता होती है। प्रभु कभी भी पूजा के मापदंड एवं भक्ति के क्रियाकलाप नहीं देखते। राम कीर्तन भी हनुमानजी को अत्यंत प्रिय है। चारों युग में अपनी कीर्ति को प्रतिष्ठित करने वाले हनुमानजी कलयुग में राम कथा होने पर यत्र-तत्र विराजमान होते है, तो हम श्रीराम नाम के उद्घोष के साथ सहज ही राम भक्त हनुमान की कृपा को प्राप्त कर सकते है।

यात्रियों की सुविधा हेतु भावनगर रेलवे मंडल के मीटर गेज सेक्शन में चल रही हैं 8 ट्रेनें

जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा एवं बेहतर रेल सेवाओं के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा मीटर गेज (MG) सेक्शन में 8 ट्रेनों का नियमित संचालन किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे यात्रियों से अपील करता है कि वे इन ट्रेन सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा का अनुभव प्राप्त करें।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, मीटर गेज सेक्शन में संचालित ट्रेनों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है—

1. ट्रेन संख्या 52949 वेरावल-देलवाडा मीटरगेज ट्रेन वेरावल स्टेशन से दोपहर 14.00 बजे प्रस्थान कर 17.50 बजे देलवाडा स्टेशन पहुंचती है।
2. ट्रेन संख्या 52955 वेरावल-जूनागढ़ मीटरगेज ट्रेन वेरावल स्टेशन से सुबह 06.15 बजे प्रस्थान कर 10.25 बजे जूनागढ़ पहुंचती है।
3. ट्रेन संख्या 52946 जूनागढ़-वेरावल मीटरगेज ट्रेन जूनागढ़ स्टेशन से सुबह 06.15 बजे प्रस्थान कर 10.25 बजे वेरावल पहुंचती है।
4. ट्रेन संख्या 52952 जूनागढ़-देलवाडा मीटरगेज ट्रेन जूनागढ़ स्टेशन से सुबह 08.00 बजे प्रस्थान कर दोपहर 14.40 बजे देलवाडा पहुंचती है।

5. ट्रेन संख्या 09595 जूनागढ़-चलाला मीटरगेज स्पेशल ट्रेन जूनागढ़ स्टेशन से सुबह 10.40 बजे प्रस्थान कर दोपहर 14.10 बजे चलाला पहुंचती है।
6. ट्रेन संख्या 52950 देलवाडा-वेरावल मीटरगेज ट्रेन देलवाडा स्टेशन से सुबह 07.50 बजे प्रस्थान कर 11.20 बजे वेरावल पहुंचती है।
7. ट्रेन संख्या 52951 देलवाडा-जूनागढ़ मीटरगेज ट्रेन देलवाडा स्टेशन से सुबह 11.00 बजे प्रस्थान कर 18.10 बजे जूनागढ़ पहुंचती है।
8. ट्रेन संख्या 09596 चलाला-जूनागढ़ मीटरगेज स्पेशल ट्रेन चलाला स्टेशन से दोपहर 14.40 बजे प्रस्थान कर शाम 17.35 बजे जूनागढ़ पहुंचती है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि यात्रियों को इन सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। ट्रेनों की समय-सारिणी का विस्तृत विवरण संबंधित स्टेशनों पर प्रदर्शित किया गया है तथा रेलवे के अधिकृत माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

भावनगर रेलवे मंडल ने विविध राजस्व में 29.51 करोड़ की आय अर्जित की,पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.6% की वृद्धि

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा विविध राजस्व (Sundry Earnings) सृजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान विविध राजस्व के रूप में 29.51 करोड़ की आय दर्ज किया गया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.6% की सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाती है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार विविध राजस्व में मुख्य परिवहन सेवाओं के अतिरिक्त स्रोतों से प्राप्त आय शामिल होती है। भावनगर मंडल का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन राजस्व स्रोतों के विविधीकरण, परिसंपत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग तथा गैर-किराया आय के साधनों को सुदृढ़ करने पर निरंतर फोकस को दर्शाता है। इस राजस्व में प्रमुख योगदान प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, भूमि एवं भवन किराया, वे-लीव शुल्क, साइडिंग रखरखाव शुल्क, विज्ञापन, पार्किंग तथा कैटरिंग से प्राप्त आय का है। अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों में गैर-रेलवे निकायों से पुराने बकाया की वसूली, अनक्लेम्ड जमा राशि तथा दंड, जुर्माना, ब्याज, निरीक्षण शुल्क एवं अन्य विविध मदों से प्राप्त आय शामिल है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने बताया कि यह उपलब्धि विभिन्न विभागों के समन्वित एवं परिणाम-केंद्रित प्रयासों के माध्यम से गैर-किराया राजस्व आधार को मजबूत करने की भावनगर मंडल की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह रिकॉर्ड विविध राजस्व न केवल सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है, बल्कि राजस्व सृजन के अभिनव उपायों की खोज तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के प्रति मंडल के प्रयासों को भी मजबूती प्रदान करता है।

04 अप्रैल 2026 से ट्रेन संख्या 19821 असारवा–कोटा द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस के समय में आंशिक संशोधन

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा में वृद्धि तथा रेल संचालन को अधिक सुचारु एवं दक्ष बनाने के उद्देश्य से अहमदाबाद मंडल की ट्रेन संख्या 19821 असारवा–कोटा द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस (बुधवार एवं शनिवार) के समय में आंशिक संशोधन किया गया है। यह परिवर्तन दिनांक 04/04/2026 (शनिवार) से प्रभावी रहेगा।

जिसका विवरण निम्नानुसार है—

ट्रेन संख्या 19821 असारवा–कोटा द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस (बुधवार एवं शनिवार) दिनांक 04/04/2026 से असारवा स्टेशन से अपने निर्धारित समय 09:15 बजे के स्थान पर संशोधित समय 08:55 बजे प्रस्थान करेगी एवं सरदारग्राम स्टेशन पर निर्धारित समय 09:20/09:21 बजे के स्थान पर संशोधित समय 09:01/09:03 बजे आगमन/प्रस्थान करेगी तथा नांदोल दहेगाम स्टेशन पर निर्धारित समय 09:40/09:42 बजे के स्थान पर संशोधित समय 09:28/09:30 बजे आगमन/प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय एवं कोच संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के कैंप हनुमान मंदिर से हनुमानजी की भव्य शोभायात्रा को प्रस्थान कराया

- मुख्यमंत्री ने दादा के आशीर्वाद लिए और रथ का पूजन कर, राज्य के नागरिकों की समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की
- गजराज, ऊंटगाड़ी, विशाल गदा, ट्रक के अलावा 'ऑपरेशन सिंदूर' का टेब्लो आकर्षण का केंद्र बना

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को अहमदाबाद के कैंप हनुमान मंदिर से भव्य शोभायात्रा को प्रस्थान कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हनुमान दादा की पूजा-अर्चना की तथा राज्य के नागरिकों की समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की।

अहमदाबाद के शाहीबाग स्थित कैंप हनुमान मंदिर ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की परंपरा के अनुसार भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। सुबह सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ के बाद इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने

हनुमानजी के रथ की आरती उतारी और उसके बाद श्रीफल (नारियल) चढ़ाकर शोभायात्रा के मुख्य रथ को प्रस्थान कराया।

उल्लेखनीय है कि; शोभायात्रा में गजराज, ऊंटगाड़ी, विभिन्न ट्रक, 'ऑपरेशन सिंदूर' का टेब्लो, विशाल गदा, भजन मंडलियों के साथ बड़ी संख्या में भक्त जुड़े। यात्रा के मार्ग पर जगह-जगह रथयात्रा का स्वागत किया गया । इस अवसर पर कैंप हनुमान मंदिर के प्रमुख सुधीरभाई नाणावटी, एडीसी बैंक के अध्यक्ष अजयभाई पटेल, मंदिर के अन्य ट्रस्टी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

गुजरात के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करती है जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल योजना

जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल में खिलाड़ियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ खेल का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है, राज्य सरकार प्रति खिलाड़ी सालाना 1.68 लाख रुपए का अनुमानित खर्च करती है

- गुजरात में 39 जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल संचालित, अब तक 12,000 से अधिक खिलाड़ियों ने उठाया लाभ
- डांग की ओपिनाबेन भिलार जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल से वर्ल्ड कप तक पहुंचीं, आज खो-खो कोच के रूप में दे रही हैं सेवाएं
- अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित प्रतिभाशाली निशानेबाज इलावेनिल वालरीवन के लिए जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल योजना बनी टर्निंग पॉइंट

जीएनएस)। गांधीनगर : अनुशासन, खेल भावना और टीम वर्क- ये ऐसे मूल्य हैं, जो कोई पाठ्यपुस्तक नहीं, बल्कि खेल का मैदान सिखाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, जो दृढ़तापूर्वक यह मानते हैं कि खेल व्यक्ति के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल (डीएलएसएस) योजना शुरू की थी। आज, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में यह योजना प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ खेल का प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी प्रतिभा को तराशने में अहम भूमिका निभा रही है।

राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करता है डीएलएसएस

खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग के अधीन कार्यरत गुजरात खेल प्राधिकरण (एसएजी) ने खेल प्रशिक्षण और स्कूली शिक्षा के दोहरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2013-14 में जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल योजना शुरू की थी। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (प्रतिभा खोज) की प्रक्रिया के अंतर्गत खिलाड़ियों का चयन दो श्रेणियों में किया जाता है, एक यंग टैलेंट और दूसरा प्रूवन टैलेंट (किसी खेल में उपलब्धि हासिल करने वाले)। चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें और स्टेशनरी, निवास, भोजन, स्कूल गणवेश, स्पोर्ट्स किट, गहन प्रशिक्षण और स्टाइपैंड जैसे लाभ दिए जाते हैं। डीएलएसएस योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल की भूमिका उल्लेखनीय रही है।

पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में डीएलएसएस स्कूल के खिलाड़ियों ने कुल 3444 मेडल और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में कुल 335 मेडल जीते हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 4 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 1 कांस्य पदक जीता है।

गुजरात में 39 जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल संचालित, योजना के तहत 2025-26 में कुल 95.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए

राज्य में जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 12,000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसका लाभ उठाया है। वर्ष 2025-26 की स्थिति के अनुसार राज्य के 29 जिलों में 39 स्पोर्ट्स स्कूल संचालित हैं और 21 विभिन्न खेलों में 5300 से अधिक खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल में खिलाड़ियों को विशेषज्ञ कोच, ट्रेनर और योग ट्रेनर द्वारा वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है, और खिलाड़ियों की फिटनेस एवं रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी उपलब्ध होते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति खिलाड़ी सालाना 1.68 लाख रुपए का अनुमानित खर्च किया जाता है। वर्ष 2025-26 में इस योजना के अंतर्गत कुल 95.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

डीएलएसएस योजना मेरे करियर के लिए टर्निंग पॉइंट बनी : अर्जुन अवॉर्डी इलावेनिल वालरीवन

निशानेबाजी में गुजरात का प्रतिनिधित्व करने वाली और अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित इलावेनिल वालरीवन पूर्व डीएलएसएस खिलाड़ी हैं। इलावेनिल ने अहमदाबाद के साणंद में स्थित लक्ष्मण ज्ञानपीठ स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर गुजरात का नाम रोशन कर रही हैं। जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल में प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अपने अनुभवों को साझा करते हुए इलावेनिल वालरीवन ने कहा, "मैंने वर्ष 2014 से 2017 के दौरान साणंद के लक्ष्मण ज्ञानपीठ स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसने एक निशानेबाज के तौर पर मेरी प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां मिली आधुनिक सुविधाओं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, विशेषज्ञ कोचिंग और निशानेबाजी के लिए उपलब्ध रेंज सेटअप से मुझे काफी मदद मिली। जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल योजना मेरे करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई।"

उल्लेखनीय है कि इलावेनिल ने 2025 की एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2024 के रियो डी जेनेरियो वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक और 2024 की जकार्ता एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। इसके अलावा, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस ओलंपिक 2024 में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

डीएलएसएस योजना की लाभार्थी डांग की ओपिनाबेन ने खो-खो विश्व कप में दिखाया कमाल

डांग जिले के बिलीआंबा गांव की रहने वाली और खो-खो खिलाड़ी ओपिनाबेन देवजीभाई भिलार भी जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल (डीएलएसएस) की खिलाड़ी रह चुकी हैं। उन्होंने खो-खो विश्व कप 2025 (भारत) में स्वर्ण पदक, 56वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप 2024 दिल्ली में स्वर्ण पदक और प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव ओडिशा 2023-24 में रजत पदक जीता है। वे 55वीं सीनियर राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप 2023 (महाराष्ट्र) तथा गोवा में 2023 में आयोजित में 37वें राष्ट्रीय खेलों में खो-खो चैंपियनशिप में भी हिस्सा ले चुकी हैं।

डांग से लेकर विश्व कप तक का सफर तय करने वाली ओपिनाबेन कहती हैं, "राज्य स्तर की खो-खो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद मेरे शिक्षक ने मुझे जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल (डीएलएसएस) योजना की जानकारी दी और उनके मार्गदर्शन से मैं वर्ष 2014 में डीएलएसएस से जुड़ गई। यहां मुझे विशेषज्ञ कोच द्वारा सुबह-शाम गहन प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इसके बाद मुझे वर्ष 2015 और 2016 के दौरान वडोदरा की एथलेटिक्स एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। राज्य सरकार की डीएलएसएस जैसी योजना के कारण ही मैं खो-खो के खेल में आगे बढ़ पाई और विश्व कप तक पहुंचने का मौका मिला। आज मैं पंचमहाल जिले में कोच के रूप में काम कर रही हूं और उभरते खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दे रही हूं।"

भावनगर के सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना में राजभाषा संबंधी निरीक्षण और हिंदी कार्यशाला का सफल आयोजन

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 31-03-2026 को भावनगर परा स्थित पश्चिम रेलवे के सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री राकेश कुमार खराड़ी के आदेशानुसार राजभाषा हिंदी से जुड़े नियमों की जानकारी देने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कारखाने के सभी अधिकारियों – कर्मचारियों ने कार्यशाला में हिस्सा लेकर अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिंदी में करने के अपने संकल्प को दोहराया।

पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय के राजभाषा विभाग की वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्रीमती सुनीता अहिरे ने दिनांक 31-03-2026 को भावनगर परा स्थित सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना में राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया। गौरतलब है कि राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार केंद्र सरकार के देशभर में स्थित कार्यालयों में संपूर्ण सरकारी कामकाज हिंदी में किया जाना चाहिए। इसी अधिनियम का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाता है।

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्रीमती सुनीता अहिरे ने भावनगर कारखाने के विभिन्न अनुभागों में जाकर सरकारी कामकाज से जुड़ी भौतिक और ई-ऑफ़िस फ़ाइलों का निरीक्षण किया और राजभाषा से जुड़े नियमों के समुचित अनुपालन पर संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने खुशी ज़ाहिर करते हुए कहा कि यह हर्ष का विषय है कि भावनगर कारखाना के कर्मचारी राजभाषा नियमों के प्रति जागरूक हैं और अपना सरकारी कामकाज हिंदी में कर रहे हैं। इस अवसर पर श्रीमती अहिरे ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत के अधिकांश नागरिक हिंदी बोलते और समझते हैं और इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यह हम सभी का संवैधानिक दायित्व है कि हम सरकारी कामकाज हिंदी में करें, ताकि आमजन से संवाद को सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाया जा सके, जिससे वे सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ बिना किसी बाधा के उठा सकें। यह कदम राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के तहत हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जारी आदेशानुसार संपूर्ण सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में किया जाना अपेक्षित है और समिति अपने निरीक्षणों के दौरान इन बातों पर कड़ी निगरानी रखती है। उन्होंने कर्मचारियों से अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने को कहा और राजभाषा नियमों के बेहतर अनुपालन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

इस अवसर पर मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री राकेश कुमार खराड़ी के आदेशानुसार राजभाषा कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, ताकि कारखाने के सभी अधिकारी-कर्मचारी राजभाषा नियमों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकें। इस कार्यशाला में वराधि श्रीमती सुनीता अहिरे ने राजभाषा नियमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उक्त कार्यशाला में कारखाने के 50 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों ने भाग लिया।

अंत में वरिष्ठ सहायक वित्त सलाहकार एवं संपर्क राजभाषा अधिकारी श्री रत्नेश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि राजभाषा कार्यशाला के माध्यम से हमें राजभाषा नियमों को विस्तार से समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। भावनगर कारखाना राजभाषा नियमों के अनुपालन हेतु हमेशा प्रतिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे पर अहमदाबाद मंडल प्रथम स्थान पर

51.13 मिलियन टन माल लदान के साथ अहमदाबाद मंडल ने भारतीय रेल में अर्जित किया 8वाँ स्थान

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के नेतृत्व में वर्ष 2025-26 के दौरान परिचालन दक्षता, माल एवं यात्री परिवहन, राजस्व सुदृढ़ीकरण तथा अवसंरचना विकास के सभी प्रमुख आयामों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित करते हुए उत्कृष्ट एवं संतुलित प्रदर्शन किया है।

वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियाँ—

- 9193 करोड़ की कुल आय अर्जित की गई, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 538 करोड़ से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
- 6867 करोड़ का माल राजस्व अर्जित किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.76% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 1814 करोड़ का कोचिंग राजस्व अर्जित किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.89% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 51.13 मिलियन टन माल लदान किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.30% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप अहमदाबाद मंडल ने भारतीय रेल में 8वाँ तथा पश्चिम रेलवे में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- वर्ष 2025-26 में 10 स्थायी गति प्रतिबंध (Permanent Speed Restriction) समाप्त किए गए।
- 26 रोड अंडर ब्रिज (RUB) एवं 04 रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण किया गया, जिससे संरक्षा एवं यातायात सुगमता में वृद्धि हुई।
- 163 किमी नई रेलवे लाइन जोड़ी गई।
- 237 ट्रैक किमी में ट्रैक्शन कार्य पूर्ण किया गया।
- 69 हाई मास्ट टॉवर स्थापित किए गए।
- 4000 रेक्स का परीक्षण किया गया, जिससे माल लदान में वृद्धि दर्ज की गई।
- कुल 17 हजार कर्मचारियों में से 2520 कर्मचारियों (लगभग 14%) को पदोन्नति प्रदान की गई, जो कर्मचारी विकास में वृद्धि को दर्शाता है।

माल लदान में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- 6,04,922 वैगनों का कंटेनर लदान किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.06% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 1,76,794 वैगनों का उर्वरक लदान किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24.61% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 1,19,948 वैगनों का नमक लदान किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 27.85% की वृद्धि दर्ज की गई।
- ऑटोमोबाइल के लोडिंग में अहमदाबाद मण्डल अग्रेसर रहा है, 42,818 वैगनों का लदान किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 11.61% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 413 एलपीजी रेक्स का लदान किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक है।

परिचालन प्रदर्शन में निरंतर सुधार

- औसतन 2893.9 वैगन प्रतिदिन लोडिंग की गई, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.77% की वृद्धि दर्ज की गई।
- कुल 72,014 कोचिंग ट्रेनें संचालित की गईं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.91% की वृद्धि दर्ज की गई।
- कुल 24,748 रेक्स लोड किए गए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.64% की वृद्धि दर्ज की गई।
- अहमदाबाद क्षेत्र में 7,049 रेक्स का संचालन किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 3.00% की वृद्धि दर्ज की गई।
- औसतन 206.20 ट्रेन प्रतिदिन इंटरचेंज किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.21% की वृद्धि दर्ज की गई।

राजस्व एवं यात्री सेवाओं में सुदृढ़ प्रगति

- 1450.67 करोड़ का गैर-भाड़ा राजस्व अर्जित किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 35.83% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- 322.82 करोड़ का स्टेशन पार्किंग राजस्व अर्जित किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 32.59% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 31.66 करोड़ का टिकट जांच राजस्व अर्जित किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 44.04% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 22.36 करोड़ का अन्य विविध राजस्व अर्जित किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 22.03% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 12.52 करोड़ का स्वच्छता दंड अर्जित किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 184.55% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- 408.10 लाख यात्रियों का परिवहन किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.16% की वृद्धि दर्ज की गई।

नई रेल सेवाएँ

- 26 मई 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वेरावल–साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई।
- 25 अगस्त 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कड़ी–साबरमती–कटोसन रोड के मध्य मेमू सेवा का शुभारंभ किया गया तथा बेचराजी से कार-लोडेड मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई।
- 16 फरवरी 2026 से असारवा–उदयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया।
- 31 मार्च 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेडब्रह्मा–हिम्मतनगर–अहमदाबाद (असारवा) नई रेल सेवा का शुभारंभ किया गया।

अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- 22 मई 2025 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सामाखियाली स्टेशन का अमृत स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया गया।
- साबरमती–बोटाद (106 किमी) रेल खंड का विद्युतीकरण पूर्ण कर गुजरात में 100% विद्युतीकरण सुनिश्चित किया गया।
- महेसाणा–पालनपुर (65.10 किमी) रेल खंड का दोहरीकरण कार्य पूर्ण किया गया।
- आंबलियासन–विजापुर–मोटी आदराज (82 किमी), कलोल–कडी–कटोसन रोड (38 किमी) तथा बेचराजी–रणुज (40 किमी) सहित विभिन्न रेल खंडों पर कार्य पूर्ण किया गया।
- 31 मार्च 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीधाम–आदीपुर रेल लाइन के मल्टी-ट्रैकिंग कार्य को राष्ट्र को समर्पित किया गया।

पश्चिम रेलवे द्वारा रचे नए कीर्तिमान, स्थापित किए नए मानक

माल ढुलाई, अवसंरचना, संरक्षा, सतत विकास एवं यात्री सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज

जीएनएस)। भारतीय रेल में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रहने वाली पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एक बार फिर उत्कृष्ट सर्वांगीण प्रदर्शन दर्ज किया है। इस अवधि में पश्चिम रेलवे ने माल ढुलाई, अवसंरचना उन्नयन, संरक्षा कार्य, उपनगरीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, यात्री सुविधाओं तथा राजस्व सृजन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। ये उपलब्धियाँ जोन के सभी विभागों के निरंतर प्रयासों तथा सुरक्षित, कुशल एवं यात्री-केंद्रित रेल संचालन के प्रति पश्चिम रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

अवसंरचना विकास

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 252 किमी नई लाइन, गेज परिवर्तन एवं दोहरीकरण कार्य पूर्ण किया गया।
- 206 रूट किलोमीटर (RKM) विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे का 100% ब्रॉड गेज नेटवर्क विद्युतीकृत हो गया है।
- पश्चिम रेलवे ने अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक कवच (संस्करण 4.0) की स्थापना पूर्ण की। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 660 RKM पर कवच तकनीक स्थापित की गई।
- वर्ष 2025-26 में पश्चिम रेलवे पर 162 रोड ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज (ROB/RUB) का निर्माण किया गया, जो भारतीय रेल में सर्वाधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 फुट ओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 मानवयुक्त समपार फाटकों का उन्मूलन किया गया।
- मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की लगभग 96% समयपालनता के साथ पश्चिम रेलवे पूरे भारतीय रेल में शीर्ष स्थान पर रहा।
- 19 स्थायी गति प्रतिबंध (PSR) हटाए गए।
- रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप, दाहोद से भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर विद्युत इंजन तैयार किया गया।
- पश्चिम रेलवे ने मिशन रफ्तार के अंतर्गत रतलाम मंडल के खाचरौद–नागदा खंड पर भारत का पहला 2×25 केवी ट्रैक्शन सब-स्टेशन सफलतापूर्वक कमीशन किया, जो रेल विद्युतीकरण एवं उच्च गति संचालन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सोना वायदा में 2281 रुपये और चांदी वायदा में 839 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 293 रुपये लुढ़का

जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 119533.65 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 31081.69 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 88450.98 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 36505 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3110.37 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 19448.07 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 149460 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 149601 रुपये और नीचे में 148550 रुपये पर पहुंचकर, 146919 रुपये के पिछले बंद के सामने 2281 रुपये या 1.55 फीसदी की तेजी के संग 149200 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 1627 रुपये या 1.36 फीसदी की तेजी के संग 121621 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 202 रुपये या 1.34 फीसदी की तेजी के संग 15238 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 148486 रुपये के भाव पर खूलकर, 149859 रुपये के दिन के उच्च और 148190 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 2159 रुपये या 1.46 फीसदी की तेजी के संग 149850 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 150000 रुपये के भाव पर खूलकर, 151725 रुपये के दिन के उच्च और 149900 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 149605 रुपये के पिछले बंद के सामने 1975 रुपये या 1.32 फीसदी की तेजी के संग 151580 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 239257 रुपये के भाव पर खूलकर, 242498 रुपये के दिन के उच्च और 238501 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 240892 रुपये के पिछले बंद के सामने 839 रुपये या 0.35 फीसदी की बढ़त के साथ 241731 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 1113 रुपये या 0.46 फीसदी की तेजी के संग 244846 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 1125 रुपये या 0.46 फीसदी की बढ़त के साथ 245011 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कमोडिटी वायदाओं में 31081.69 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 88450.98 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 19448.07 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36505 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 2345.22 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 1.7 रुपये या 0.15 फीसदी की बढ़त के साथ 1165.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 1.55 रुपये या 0.49 फीसदी की मजबूती के साथ 321 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 2.95 रुपये या 0.84 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 353.55 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 10 पैसे या 0.05 फीसदी चढ़कर 195.2 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 9277.14 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 9675 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 9844 रुपये और नीचे में 9029 रुपये पर पहुंचकर, 293 रुपये या 3.06 फीसदी गिरकर 9274 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 291 रुपये या 3.04 फीसदी औंधकर 9272 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 273 रुपये के भाव पर खूलकर, 275.5 रुपये के दिन के उच्च और 268.7 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 274.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 5 रुपये या 1.82 फीसदी की गिरावट के साथ 269.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 5 रुपये या 1.82 फीसदी गिरकर 269.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 1050 रुपये पर खूलकर, 10 पैसे या 0.01 फीसदी टूटकर 1043.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 13476.96 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 5971.11 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1379.72 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 731.92 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 11.61 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 221.97 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7926.53 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1312.80 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 7643 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 52139 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26382 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 344815 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 52266 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6988 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 18978 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 73176 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20195 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 33318 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा 36001 पॉइंट पर खूलकर, 36505 के उच्च और 36001 के नीचले स्तर को छूकर, 614 पॉइंट बढ़कर 36505 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 12000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 71.9 रुपये की गिरावट के साथ 168.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.05 रुपये की गिरावट के साथ 15.35 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 48.5 रुपये की गिरावट के साथ 202.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 163 रुपये की गिरावट के साथ 1686.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 27 पैसे की नरमी के साथ 18.5 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 325 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.64 रुपये की बढ़त के साथ 5.5 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 38.5 रुपये की बढ़त के साथ 263.9 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.45 रुपये की बढ़त के साथ 16.65 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 120000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 367.5 रुपये की गिरावट के साथ 288 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 466.5 रुपये की गिरावट के साथ 1351 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 49 पैसे की नरमी के साथ 11.53 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 307.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 11 पैसे के सुधार के साथ 2 रुपये हुआ।